

मैनुअल प्र सं 43/2022  
जीसीएमएस 2022/176

1. मूलाराम पुत्र मूलाराम (माता गुडडी पत्नी मूलाराम पुत्री मनफूल) जाति मेघवाल निवासी 50 एनपी (ततारसर) तहसील राजसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. सुमन देवी पुत्री मूलाराम पत्नी बादल सिंह (माता गुडडी पत्नी मूलाराम पुत्री मनफूल) जाति मेघवाल निवासी 50 एनपी (ततारसर) हाल 2 कैएम तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर

- प्रार्थीगण

1. गुडडी पुत्री मनफूल पत्नी मूलाराम जाति मेघवाल निवासी 50 एनपी (ततारसर) हाल 6 डीडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर
2. गोपीराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी 6 डीडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व राजसिंहनगर

- अप्रार्थीगण

उपस्थिति :- अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

1. श्री मगतूराम नायक, श्री जितेन्द्र सोनी, वकील प्रार्थीगण
2. श्री संवेन्द्र बिश्नोई, वकील अप्रार्थी सं. 1-2

-: निर्णय :-

दिनांक : 16.08.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाना मनफूल पुत्र चुन्नीराम जाति मेघवाल निवासी 50 एनपी के नाम से चक 50 एनपी के मु.नं. 52 प.नं. 230/339 के कि.नं. 21/2, 22 ता 25 सालम सालम कुल 1.054 है. वारानी भूमि व मु. नं. 23 प.नं. 239/336 कि.नं. 17/2, 18 ता 25 सालम सालम कुल 2.025 है. नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज थी। उनकी मृत्यु के पश्चात भूमि का विरास्तन इतकाल माता अप्रार्थी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया। अप्रार्थी सं. 1 के तीन वारिस हैं। उपरोक्त भूमि जो नाना मनफूल से आई थी। जिसमें प्रत्येक वारिसान का प्रार्थी सं. 1-2 व अप्रार्थी सं. 1-2 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा बनता है। नाना की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त भूमि का विरास्तन इतकालमाता ने केवल मात्र अपने नाम से करवा लिया जबकि भूमि में प्रार्थीगण 1/4 विरास्तन हक व हिस्से के अधिकारी थे। माता की काफी उम्र हो चुकी है तथा उसके सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो चुकी है। इसी का नाजायज फायदा अप्रार्थी सं. 2 जो प्रार्थीगण का भाई है। उसने अपने प्रभाव में माता को जबरन अपने पास रख रखा है तथा विरास्तन भूमि को बेचान करने की फिराक में है। जिसको लेकर उसने बिकवाली निकाल रखी है। कल दिनांक 28.03.2022 को चक 50 एनपी में कुछ लोगों को व अप्रार्थी सं. 1 को साथ लेकर आया व भूमि को बेचान करने के वाबत लोगों को दिखा रहे थे। प्रार्थीगण भी उस भूमि में थे। तब अप्रार्थीगण वहां आये। अप्रार्थीगण व उनके साथ आये लोगों ने कहा कि हम इस भूमि को बेचान कर रहे हैं। तब गांव के मौत विरान लोगों को बुलाकर भूमि को बेचान नहीं करने से समझाया तो अप्रार्थीगण ने एलानिया धमकी दी कि शीघ्र ही उपरोक्त विरास्तन भूमि को बेचान करके तुम्हें भूमि से बेदखल कर देंगे। उसमें खड़ी फसल जो काशत कर रखी है उसे निकाल कर ले जायेंगे यदि ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए तो फसल नष्ट कर देंगे। ऐसी धमकी देकर अप्रार्थीगण वहां से चले गये। यही विनाय वाद कारण प्रार्थीगण को प्राप्त है। विवादित भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण कि प्रार्थीगण के कब्जा काशत व पानी की बारी व

उपखण्ड अधिकारी  
राजसिंहनगर



यदि वकील उभयपक्ष सूची मयी। वकील प्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थीगण की माता अप्रार्थीया सं. 1 का जनक पिता की मृत्यु के उपरान्त विरास्तन प्राप्त हुई है। अप्रार्थीया सं. 1 के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 के बीच विवाद है। विवादित विवादित भूमि में प्रत्येक का 1/4 हिस्सा विरास्तन बनना है। प्रार्थीया अपात्री सं. 2 के कथन से प्रकृत प्रार्थीगण का जनक हिस्सा की भूमि में वीरम बहाल की विधि में है। यदि वे सामग्यवत् तो कहें तो प्रार्थीगण का अपूर्ण्य ही प्रार्थीगण का अपूर्ण्य ही है। विवादित भूमि में प्रार्थी सं. 1, 2 अपनी बहस में तब प्रार्थीया पत्र प्रार्थी सं. 2 पर प्राप्त होने के बाद विधिक विमत के उपरान्त अप्रार्थीया के नाम से प्रार्थी सं. 2 को देई है। विवादित भूमि अप्रार्थीया की एकल स्वातदारी भूमि है जिसमें प्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीया की देखागत भी नहीं की जाती है। प्रार्थी सं. 1 पक्ष में बहस लिया है। प्रार्थीगण सदभावी नहीं है। न ही क्वीनहेण्ड से न्यायालय में अप्रार्थीया के विरुद्ध प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण के विरुद्ध अरथाई निषघाजा पारित कर दी जाती है तो अप्रार्थीया को अपूर्ण्य क्षति होगी। जिसका मूल्य में नहीं आका जा सकेगा। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलाकन किया। विवादित भूमि चक 50 एनपी जमावंदी संवत् 2075-2078 के खाता सं. 20 में दर्ज अनुसार मु.नं. 52 व 23 की कुल 3.079 है। वारानी नहरी गुडडी पुत्री मनफूल जाति मेघवाल सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ चित्रप्रति नामान्तरण सं. 136 ग्राम 50 एनपी स्वीकृत दिनांक 05.09.1998 की प्रस्तुत की हैं जिस अनुसार मु.नं. 4 की 1.341 है। नहरी, 23 की 4.505 है। नहरी, 52 की 3.162 है। वारानी भूमि मनफूल वल्द चुनी से विरास्तन रुकमा बेवा मनफूल 1/3 हिस्सा, गुडडी, दुखतराम 2/3 हिस्सा व.हि.व. खातेदार दर्ज हुई हैं।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के नियम 14 में प्रावधान हैं कि -  
"हिन्दू नारी की सम्पत्ति उसकी आत्यंतिकतः अपनी सम्पत्ति होगी - (1) हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा में सम्पत्ति के अन्तर्गत वह जंगम और स्थावर सम्पत्ति आती है जो हिन्दू नारी ने विरास्त द्वारा अथवा वसीयत द्वारा विभाजन में अथवा भरण-पोषण के या भरण-पोषण की बकाया के बदले में अथवा अपने विवाह के पूर्व या विवाह के समय या पश्चात् दान द्वारा किसी व्यक्ति से, चाहे वह सम्बन्धी हो या न हो, अथवा अपने कौशल या परिश्रम द्वारा अथवा क्रय द्वारा अथवा चिरभोग द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से, चाहे वह कैसी ही क्यों न हो, अर्जित की हो और ऐसी सम्पत्ति भी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व स्त्रीधन के रूप में उसके द्वारा धारित थी।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसी किसी सम्पत्ति को लागू न होगी जो दान अथवा विल द्वारा या अन्य किसी लिखत के अधीन सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन या पंचाट के अधीन अर्जित की गई हो यदि दान, विल या अन्य लिखत अथवा डिक्री, आदेश या पंचाट के निबन्धन सम्पदा विहित करते हों।"

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भी अंकित किया गया है कि विवादित भूमि अप्रार्थीया सं. 1 को विरास्तन प्राप्त हुई हैं, एवं विरास्तन भूमि में रो ही अपने हक एवं अधिकारों के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत अप्रार्थीया सं. 1 को प्राप्त विरास्तन भूमि में अप्रार्थीगण

का हक हिस्सा होने का कथन करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 की उपधारा 1 के प्रावधान अनुसार विवादित भूमि अप्रार्थीया को प्राप्त स्त्रीधन की परिभाषा में आती हैं, जिसकी अप्रार्थीया पूर्ण स्वामी की हैसियत से उपयोग उपभोग करने की अधिकारिणी हैं। विवादित भूमि अप्रार्थीया स 1 के नाम से खातेदारी दर्ज हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीया के पक्ष में है। विवादित भूमि अप्रार्थीया द्वारा स्त्रीधन एवं पूर्ण स्वामी के रूप में धारित करने के कारण सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीया के पक्ष में है। रिकार्डेड टिनेंट के विरुद्ध यदि निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थीया को क्षति होने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति निषेधाज्ञा के तीनों कारक अप्रार्थीया के पक्ष में हैं, प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित है।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता हैं, तथा न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30.03.2022 को भी निरस्त किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(सुभाष चन्द्र)

आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर